

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-288/2011।

विमलादेवी पत्नी जायन्दा जाति जाट निवासी जेरठी तहसील व जिला
सीकर ॥ राज० ॥

---अपीलान्ट---



- 1- अशोककुमार तथा कथित दत्तक पुत्र छत्रराम जाति जाट निवासी ग्राम
2- भगोती पुत्र छत्रराम पत्नी बजरंगलाल जेरठी तहसील व जिला
सीकर ॥ राज० ॥
3- गीता पुत्री छत्रराम
4- दलु पत्नी छत्रराम
5- उप पंजीयक सीकर।
6- तहसीलदार सीकर।

सत्यमेव जयते

---रेस्पोंडेन्ट्स---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं फंडी
दिनांक 14-9-2011 द्वारा
सहायक कलेक्टर ॥ द्वितीय ॥ सीकर।

उपस्थिति-

- 1- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री बनवारीलाल बरवड एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट सं०-1
3- श्री राकेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट सं०-3

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोंडेन्ट सं०-
1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा तथा
रेकार्ड संशोधन का पेशा कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं०- 2
व 3 स्वर्गीय छत्रराम के वंशज है। छत्रराम के दो जायन्दा पुत्रीयां वादी सं०-2
व प्रतिवादी सं०-2 है। स्व० छत्रराम व प्रतिवादी संख्या-3 के कोई जायंदा

पुत्र न होने के कारण उन्होंने वादी को बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था। जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 25-2-1989 को वादी के हक में विधिवत पंजीकृत करवा दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं०-2 की पैतृक आराजी ख०नं० 266 रकबा 0.07 हैक्टर, ख०नं० 267 रकबा 2.77 हैक्टर वाले ग्राम जेरठी तहसील सीकर में स्थित है जिसका पूर्व में खाता वादीगण के दादा भोजाराम पुत्र मानाराम का था। वादीगण के पिता छतुराम का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो गया था। भोजाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का नामान्तरकरण सं०-866 दिनांक 5-3-2009 को बसाजिहा प्रतिवादी सं० 2 व 3 वादी सं०-1 का नाम जानबूझकर अंकित नहीं करवाया। नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन की आड़ में प्रतिवादी सं०-2 व 3 ने दिनांक 18-5-2009 को वाद ग्रस्त भूमियों ख०नं० 266 व 267 कुल रकबा 2.84 हैक्टर में से 0.059 हैक्टर में से 2/3 हिस्सा का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं०-1 के हक में निष्पादित एवं पंजरकृत करवा दिया जो सर्वथा ~~वैध~~ अवैध व शून्य है। उक्त आराजी में छतुराम का मात्र रकबा 0.059 हैक्टर रहा है। जिनमें से वादी एवं प्रतिवादी सं०-2 व 3 का समान हक हिस्सा है। शेष रकबा अन्य सह-खातेदारों का है। जिसका कोई विवाद नहीं। किन्तु प्रतिवादी सं०-1 प्रतिवादी सं०-2 व 3 की मदद से वादीगण को उसके कब्जा काश्त से बेदखल कर आराजी का ओर अन्तरण करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। दिनांक 27-5-2009 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर से बेदखल करने की धमकियां देने तथा विक्रय करने की कुयेष्टा से वादी को वाद कारण पैदा हुआ जिस पर यह दावा पेश किया गया। अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी के 1/4 हिस्से का वादी सं०-1 वादी सं०-2 व प्रतिवादी सं०-2 व 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।



योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत साक्ष्य, रेकार्ड, जबाब दावा का सही रूप से अवलोकन नहीं करके वास्तविक स्थिति को समझे बिना आदेश पारित कर कानूनी भूल की है । अदालत मातहत के समक्ष मुख्य विवाद रेस्पोंडेंट संख्या-1 अशोक कुमार का मृतक छतुराम का दत्तक पुत्र होने के सम्बन्ध में था । जिसने गोदनामा दिनांक 25-2-1989 का प्रस्तुत किया है । जो रेस्पोंडेंट सं0-4 दलु द्वारा अशोककुमार को दत्तक लेना बताता तथा स्पष्ट रूप से मना भी किया है । गोदनामा से भी गोद पुत्र साबित नहीं है । छतु की मृत्यु सन् 1980 के पूर्व हो गयी थी। जिसके कानूनी वारिशा रेस्पोंडेंट संख्या-2, 3 व 4 ही है जो नामान्तरकरण सं0-866 दिनांक 5-3-2009 से साबित है । यह गलत था तो अपील में चुनौती देना चाहिये था । किन्तु नामान्तरकरण सं0 866 की कोई अपील पेश नहीं की । विवादित आराजी रेस्पोंडेंट संख्या-4 की स्वअर्जित है । जिसको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-14 के अनुसार एक विधवा को अपनी आराजी को वसीयत, दान, विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। जिससे रेस्पोंडेंट सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट को दिनांक 18-5-2009 को बैचान कर दिया और कब्जा करवा दिया। अपीलान्ट मौके पर काबिज है । अदालत मातहत ने बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये रेस्पोंडेंट/वादी का दावा विधि विरुद्ध डिक्री किया है । रेस्पोंडेंट संख्या-1 को रेस्पोंडेंट संख्या-4 के जीवनकाल में कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते और ना ही अशोक कुमार को दावा पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं है । अदालत मातहत ने केवल मात्र स्कूल के प्रमाण पत्र पर ही दत्तक पुत्र मान लिया जिस को प्रदर्श मार्क भी नहीं किया है । अशोक कुमार का पिता बजरंगलाल चालाक किस्म का व्यक्ति है जो अपनी सास दलु की सम्पत्ति को हड़पना चाहता है । मतदाता सूची में भी आजतक बजरंगलाल अशोक कुमार दर्ज है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पॉन्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर ३ रा मिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं०- 2062 से 2065 में ख०नं० 266, 267 कुल किता-2 रकबा 2.84 हैक्टर पर नामान्तरकरण सं०-866 दिनांक 5-3-2009 से भोजा हि०। की विरासत भागोती, गीता पुत्री छतू, दलु पत्नी स्व० छतू हि० रकबा 0.0591 हैक्टर, कुरडाराम पुत्र नारायण हि० 0.0592 हैक्टर, रिछपाल भगवाना कानाराम नेमीचन्द पि० ३ यामाराम रतनी पत्नी स्व० ३ यामाराम हि० रकबा 0.0592 हैक्टर हिस्सा। स्वीकार हुआ। नामा सं०-866 दिनांक 5-3-2009 में भोजा पुत्र माना के फोट होने पर भागोती गीता पुत्री छतू दलु पत्नी छतू हि० 0.0591 हैक्टर, कुरडाराम पुत्र नारायण हि० 0.592 हैक्टर, रिछपाल भगवाना कानाराम नेमीचन्द पि० ३ यामाराम, रतनी पत्नी ३ यामाराम हि० 0.0592 हैक्टर का स्वीकार किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 18-3-2009 में गीता, दलु ने ख०नं० 266, 267 कुल किता-2 रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि में दर हिस्सा। आना भूमि में से रकबा 0.0591 पूर्ण हैक्टर भूमि में से विक्रेता गीता व दलु ने अपना 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण बिमलादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह काजला को विक्रय किया है। गोदनामा दिनांक 25-2-89 में दलु पत्नी छतू ने अशोककुमार पुत्र बजरंग लाल को गोद लेना गोदनाम में तस्दीक किया है। पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर आया दिनांक 31-7-2009 को पत्रावली प्रतिवादी सं०-2 व 3 की तलबी में विचाराधीन रहीं। इनकी तलबी हुई अथवा नहीं प्रतिवादी सं०-2, 3 अदालत मातहत में हाजिर हुये अथवा नहीं कोई अंकन नहीं। दिनांक 14-9-2011 को प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 3 ने अपना जबाब दावा पेश किया। इसी दिन अदालत मातहत ने जबाब दावा लेकर अपना निर्णय पारित किया है। वादीगण का दावा उद्घोषणा, स्थायी छिछे

दावे में दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयों का निर्धारण किया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित मार्क करते हुये प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय किया जाना चाहिये था। इसके समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर आरएलडब्लू 2009॥१॥राज० पेज-387, ०००, आरआरटी 2009-10॥एस०सी०॥ पेज-485, आरआरटी 2014॥2॥ पेज-1157 व 1136 पेशा की जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि दावा व जबाब दावा के आधार पर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी के अनुसार तनकीयों का निर्धारण किया जावे तथा इसके बाद साक्ष्य सबूत लेकर आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय किया जाना चाहिये। इनके विपरित रेस्पोंडेंट ने कोई जबाब पेशा नहीं किया बल्कि यही कहा कि जहां पर मैरिट प्रबल हो वहां पर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी व आदेश 20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तर्क को हम उचित नहीं मानते। प्रस्तुत नजीरों में स्पष्ट किया गया है कि दावे में तनकीयों का निर्धारण कर तनकीवाईज निर्णय किया जाना ही उचित एवं विधिक है। इससे न्यायालय सहमत है। दूसरा बिन्दू अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 18-3-2009 से गीता व दलु का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा क्रय किया है। अपीलान्ट एक सद्भावी क्रेता है। इस विक्रय पत्र को रेस्पोंडेंट ने कहीं चैलेंज किया हो ऐसा भी कोई उच्च विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में नहीं बताया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में गोदनामे के आधार पर रेस्पोंडेंट को छतु का भागोती, गीता व दलु के बा चौथे नम्बर पर वारिस मानकर उक्त आराजी में अशोक कुमार का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। इस सम्बन्ध में दावे का जबाब दावा पेशा होने पर जब दावे का विरोध किया गया है तो कानूनन प्रस्तुत नजीरों के अनुसार तनकीयों का निर्धारण किया जाना चाहिये तथा बाद साक्ष्य सबूत आदेश 20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार तनकीवाईज निर्णय किया जाना। इस पर हम विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों से सन्तुष्ट है। तथा जिन दिन

जबाब दावा पेशा किया गया उसी दिन दावे का निर्णय किया गया जो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। इससे भी स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया है। इस कारण हम अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-9-2011 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण व वे वादीगण से साक्ष्य सबूत लेकर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी एवं आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना करते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-8-2018 को उपस्थित हों।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया।


१ अंवरलाल मेहरड़ा १

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर